भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5746

गुरूवार, 2 मई, 2013

पीएसयू के कर्मचारियों को वेतन

5746. प्रो. सौगत राय:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच माहों से सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है या इसके भुगतान में विलंब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पीएसयू के नाम क्या हैं तथा प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और आज की तारीख तक वेतन की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ग) समय पर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं एवं इन मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सभी पीएसयू के निजीकरण एवं उनकी देयताओं के भुगतान के लिए उनकी परिसंपत्तियों के बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड़.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) भारी उद्योग विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों को अक्टूबर, 2012 से वेतन का भुगतान नहीं किया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	कर्मचारियों की संख्या	बकाया वेतन की राशि
1.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	1105	18.85
2.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	54	0.78
3.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	65	1.38
4.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	131	1.34
5.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	93	1.08
6.	नेपा लिमिटेड	1178	17.96
7.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1832	43.73
8.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. क. लिमिटेड	687	4.72
	कुल	**5145**	**89.84**

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम रुग्ण / हानि उठाने वाले उद्यम हैं और ये अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों को अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए योजनेतर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस 8 उपक्रमों को दिनांक 1.4.2012 से 30.9.2012 तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए मार्च, 2013 में 81.92 करोड़ रुपए का योजननेतर ऋण मंजूर किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ड़.) प्रश्न नहीं उठता।